श्री राजनीति प्रसाद: *

श्री सभापति: आज ज़ीरो आवर नहीं है...(व्यवधान)... You will not argue with the Chair. आप बैठ जाइए...(व्यवधान)... Please assist the Chair. ...*(Interruptions)*... Please allow the question to be answered. ...*(Interruptions)*... This is not going on record. You are wasting your breath. ...*(Interruptions)*... This is not going on record. You are wasting your breath. ...*(Interruptions)*... आप लोग बैठ जाइए...(व्यवधान)... It is not being televised. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: *

MR. CHAIRMAN: This is not being televised. ...*(Interruptions)*... This is not going on record. ...*(Interruptions)*... Please save your breath and get on with the scheduled business. ...*(Interruptions)*... Venkaiahji, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: *

श्री सभापति: प्लीज़, पासवान जी, आप बैठ जाइए...(व्यवधान)... Question No. 421 please. ...*(Interruptions)*...

Centrally sponsored schemes in Bihar

*421. SHRI RAM KRIPAL YADAV: Will the MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of funds allocated under the centrally sponsored schemes of the Ministry to Bihar during the financial years 1998-2004 and 2004-10, scheme-wise and year-wise;

(b) the funds that have been released against the allocation during this period, scheme-wise and year-wise; and

(c) the details of amount already spent by the State Government of Bihar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI SAUGATA RAY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) There were three Centrally Sponsored Schemes of Ministry of Urban Development under implementation in Bihar, *viz*., Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT), Accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP) and National Urban Information System (NUIS) during the period from 1998 to 2010. The details of funds allocated, released and spent by State Government of Bihar, scheme-wise and year-wise are enclosed as Statement-I.

*Not recorded.

Statement-I

Year-wise details of funds under Centrally sponsored schemes for Bihar

(Rupees in lakhs)

Name of Scheme	Upto 1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
IDSMT													
Funds allocated	State-wise allocation not made												
Funds released	806.89	20.00	00.00	30.00	200.49	90.00	317.00	323.83	74.91	299.06	**	**	**
Funds spent*	890.79	133.62	14.62	00.00	50.59	35.36	16.13	00.00	170.6	256.07	—	—	—
AUWSP													
Funds allocated	401.79	192.75	313.21	308.4	261.96	394.32	386.05	413.63	No specific State-wise allocation			—	—
Funds released	262.37	192.75	319.47	0.00	0.00	419.05	386.05	219.87	687.69	392.95	46.87	**	**
Funds spent	As per utilization certificate submitted by the State, an unspent amount of Rs. 79.91 lakh is lying with the State Government												
NUIS													
Funds allocated	—	—	—	—	—	—	—	—	111.22	—	—	—	—
Funds released	—	—	—	—	—	—	—	—	37.08	—	18.525	—	—
Funds spent	—	—	—	—	—	—	—	—	Utilization certificate not received				

Figures upto 2000-01 include those for Jharkhand State also.

*Under IDSMT expenditure includes State and ULB share also.

**Schemes subsumed in Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM).

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पूरे बिहार राज्य के, खास तौर पर जो शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, उनके संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वे स्कीम्स हैं– IDSMT, AUWSP, NUIS. उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि इसी स्कीम में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन भी मिला दिया गया है।

सर, जब UPA-I Government ने यह महसूस किया कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाली अरबन पॉपुलेशन के लिए एक विशेष राशि आवंटित की जाए ताकि उनका जीवन-स्तर ऊपर उठ सके, उसी दरम्यान जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 63 शहरों का चयन किया गया। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पटना, जहाँ से मैं आता हूं, पटना और बोधगया, बिहार के दो शहर, इस स्कीम के अंतर्गत लिए गए हैं। चूँकि उस योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है, इसका कोई उल्लेख मंत्री जी ने इसमें नहीं किया है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहता हूँ कि बोधगया और पटना शहरों के लिए आपने कितनी राशि आवंटित की और उसमें से कितनी राशि इनके डेवलपमेंट के लिए खर्च की गई? उसके साथ-साथ...

श्री सभापति: आप एक बार में एक ही सवाल पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। यह उसी में है। जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में 50 हजार करोड़ रुपए पूरे देश के लिए और शहरों के विकास के लिए 6300 करोड़ रुपए थे। उसी में 2000 करोड़ रुपए गरीबों के आवास के लिए भी थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसमें से कितनी राशि आपने आवंटित की और उसमें से कितनी राशि बिहार की सरकार अब तक खर्च कर पाई है?

SHRI SAUGATA RAY: Sir, in Bihar, 2 cities have been included under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission as Mission Cities, Patna and Bodh Gaya, which the hon. Member pointed out. The total Central allocation for 7 years for Bihar is Rs. 592.41 crores. This is under the Urban Infrastructure and Governance. There is a separate scheme under the JNNURM which is called the BSU, Basic Services for the Urban Poor, which is run by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. So, out of Rs. 592.41 crores, 8 projects have been sanctioned, and the total ACA committed is Rs. 394.8 crores, which means that Bihar has still available funds around Rs. 198 crores for which it can still submit projects.

श्री राम कृपाल यादव: सर, यह दुर्भाग्य है कि भारत की सरकार ने जो राशि आवंटित की उसका उपयोग राज्य सरकार ने नहीं किया, इसीलिए कि वह DPR नहीं बना सकी। वहाँ सुशासन की सरकार चल रही है, यह बात सही है।

मैं दूसरे प्रश्न में यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि केन्द्रीय संस्थान, जो कि एक संवैधानिक संस्थान है, उसके माध्यम से यह खबर आई है कि जो केन्द्र प्रायोजित योजना है, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने क्या इसकी कोई जानकारी प्राप्त की है कि आपके द्वारा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत जो 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है, उस पैसे में भारी तौर पर लूट हुई है? क्या इसकी जानकारी आपको है और अगर नहीं हुई है तो क्या आप इसकी जाँच कराएँगे?

श्री **सौगत राय**: माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम कृपाल यादव: सर, यह पूरे देश को खबर है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम कृपाल यादव: माननीय हाई कोर्ट ने सीबीआई की जाँच के लिए कहा है और आपको इसकी खबर नहीं है! आप पैसा दे रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है! ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: इस पर discussion नहीं होगा...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये।

श्री **राम कृपाल यादव**: आप जनता की राशि आवंटित कर रहे हैं, उसकी लूट हो रही है और आप कह रहे हैं कि कोई खबर नहीं है! ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए, इस पर discussion नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)... What is the question? ...*(Interruptions)*... प्रो. अनिल कुमार साहनी...(**व्यवधान**)...

श्री राम कृपाल यादव: इसको पूरे देश के लोग जान रहे हैं...(**व्यवधान**)... सर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है...(**व्यवधान**)... आपके सरकारी खजाने के पैसे की लूट हो रही है और आप कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है! ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: What is the issue here? ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए।

श्री राम कृपाल यादव: *

MR. CHAIRMAN: This is not going on record. Prof. Anil Kumar Sahani.

प्रो. अनिल कुमार साहनी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि बिहार में शहरी विकास के लिए जो आवंटन दिया जाता है, क्या वह अन्य राज्यों से कम है? वहाँ अन्य राज्यों की तुलना में कितनी कम राशि दी जाती है? क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के शहरों का विकास नहीं होना चाहिए? अन्य राज्यों को जो पैसा आप देते हैं..

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

प्रो. अनिल कुमार साहनी: सर, यह मेरा डायरेक्ट सवाल है कि बिहार को कितनी कम राशि दी जा रही है? अभी हमारे राम कृपाल बाबू ने काम के संबंध में जो कहा है, वह काम वहाँ पर दिखायी पड़ रहा है। वहाँ सारा काम नगर निगम के द्वारा होता है। ...(**व्यवधान**)... उसका जवाब दीजिए।

श्री सभापति: आप सवाल पूछ चुके हैं। थैंक यू। अब आप बैठ जाइये।

श्री सौगत राय: सर, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि बिहार को कम दिया जाता है कि नहीं। Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission में एक principle है कि Million Plus Cities, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वे इस मिशन के अंदर हैं।

मैंने जैसा पहले बताया कि इसमें 8 प्रोजेक्ट्स approve किये गये और 594 करोड़ रुपये अलॉकेट किये गये। इसके अलावा, एक दूसरी स्कीम, Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMST) भी है। इसमें 11 प्रोजेक्ट्स दिये गये हैं। उसके लिए 254 करोड़ रुपये का अलॉकेशन है और उसमें 209 करोड़ रुपये अभी तक committed है। इसका मतलब यह कि अभी भी 45 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला है।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Ram Vilas Paswan.

श्री रामविलास पासवान: सर, मैंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखा था। उसके जवाब में उन्होंने हमको बतलाया कि 2001 से 2004 तक, जब एनडीए की सरकार थी...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Put questions only, whoever it may be. ...*(Interruptions)*... Ask the question. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए। ...(**व्यवधान**)... देखिए, यह supplementary है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़।

श्री रामविलास पासवान: मैं supplementary ही पूछ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा जो मूल प्रश्न है, वह यह है कि उस समय 2,939 करोड़ रुपये दिये गये थे और जो यूपीए-। की सरकार आयी, उसने चार सालों में 18,957 करोड़ रुपये दिये। ...(**व्यवधान**)...

*Not recorded.

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री रामविलास पासवान: सर, एनडीए की सरकार ने जो बिहार को दिया उससे 6 गुना...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री रामविलास पासवान: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि जो पैसा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दिया गया है, उसमें से भारी संख्या में पैसे को डायवर्ट किया गया है? जो 1 करोड़ 24 लाख जॉब काड्र्स बने थे, उनमें से केवल 41 लाख लोगों को ही रोजगार मिला है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... Please let it be answered.

श्री सौगत राय: सर, इस प्रश्न का मूल प्रश्न के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह हमारे दफ्तर से संबंधित नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Naresh Chandra Agrawal.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि Jawaharlal Nehru Urban Development Mission, जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक लाख से ज्यादा की आबादी के जो शहर हैं, उनको उसमें चयनित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मात्र सात शहर चयनित किये गये हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से ऊपर शहरों का...

श्री सभापति: देखिए, सवाल बिहार के ऊपर है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: श्रीमन्, हम पॉलिसी के ऊपर पूछ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह पॉलिसी इश्यू नहीं है। यह बिहार के ऊपर सवाल है। आप इस पर supplementary पूछिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: श्रीमन्, यह urban-centred scheme के संबंध में है।

MR. CHAIRMAN: In Bihar.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: यह in Bihar है, लेकिन जो principally है, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें शहरों को चयनित किया गया है। इसमें कितनी आबादी के ऊपर के शहरों को चयनित किया गया है, यह माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है। चूंकि वह सदन की property बन गई, इसलिए उस जवाब से संबंधित प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली बिहार तक इसको सीमित रखा जाए...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप देखिए कि जवाब क्या है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सभापति जी, बहुत दिनों तक हम उत्तर प्रदेश तक सीमित रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप जवाब देखिए कि "under implementation in Bihar". देखिए, नरेश जी, इस पर discussion नहीं हो सकता। This is not the time for discussion.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: चलिए, मैं इस पर दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी आवास योजना, जो Centrally-sponsored scheme है, उसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने यह शर्त रखी है कि जिन राज्यों में यह योजना दी जाएगी, वहां ज़मीन देने का दायित्व राज्य सरकार का होगा। मैं जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा है, तो क्या मंत्री जी इस प्रकार के आदेश को वापस लेते हुए ज़मीन देने का दायित्व राज्य सरकार की जगह, केन्द्र सरकार के ऊपर रखेंगे, यदि हां, तो वे कब तक ऐसे आदेश जारी करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सौगत राय: सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने राजीव आवास योजना के बारे में घोषणा की है, लेकिन उसकी guidelines अभी final नहीं हुई हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: नहीं, सभापति जी, स्टेट्स के पास लिखकर पहुंच गई हैं, मंत्री जी कैसे यह कह रहे हैं? माननीय शैलजा जी यहां बैठी हैं, वे बता दें...(**व्यवधान**)... शैलजा जी, इसका जवाब दे सकती हैं, यह स्कीम उनकी मिनिस्ट्री से sponsored है। अगर मंत्री जी को मालूम नहीं है, तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि उन्हें इसका जवाब मालूम नहीं है, लेकिन वे सदन को गुमराह नहीं कर सकते ...(**व्यवधान**)... वे सदन को गुमराह नहीं कर सकते। मुझे इसमें आपका संरक्षण चाहिए ...(**व्यवधान**)... वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। संबंधित मंत्री यहां बैठी हुई हैं...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: All right. Let it be answered.

श्री सौगत राय: सभापति जी, जैसा मैंने पहले बताया कि राजीव गांधी आवास योजना की guidelines अभी final नहीं हुई हैं। इस साल 60 करोड़ रुपया हर प्रांत को plan final करने के लिए दिया गया है। वैसे यह सवाल हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सवाल Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation से ताल्लुक रखता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सभापति जी, यह centrally sponsored scheme है, मुझे आपका संरक्षण चाहिए...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No more supplementaries. ...*(Interruptions)*... Question No. 422.

MRTS in Chennai

*422. SHRI N. BALAGANGA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the total funds allocated for the Mass Rapid Transit System (MRTS) in Chennai, during the last three years and in the current year so far;

(b) the total funds utilized so far for this project, during the said period;

(c) by when this project is likely to be completed; and

(d) the likely allocation of funds during in the remaining Eleventh Plan period and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI SAUGATA RAY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Chennai Metro Rail Ltd. (CMRL) has reported that the total funds allocated for the Mass Rapid Transit System (MRTS) in Chennai, during the last three years and in the current year so far by Government of India (GoI) and Government of Tamil Nadu (GoTN) are as under:—

(Rs. in crore)

Source of funding	During the last 3 years	Current year (2010-11)—BE
Government of India	152.79	652.00
Government of Tamil Nadu	1050.00	600.00
TOTAL:	1202.59	1252.00